



## झुन्झुनू जिले में सतत विकास हेतु पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता एवं उपागम

डॉ. बंशीधर<sup>1\*</sup> एवं श्रीमती सविता<sup>2</sup>

<sup>1</sup> सहायक आचार्य-भूगोल विभाग, श्री श्रदानाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टोडी (गुढा गौडजी) झुन्झुनू, राजस्थान.

<sup>2</sup> संशोधनकर्ता एवं अध्यापिका

### सार:—

मानव तथा पर्यावरण के मध्य सम्बन्ध सुधार की प्रक्रिया ही पर्यावरण प्रबन्धन है। मानव और प्रकृति के बीच जब संबंध मधुर होंगे तो प्रकृति से जितना हम लेंगे अथवा जितना दोहन करेंगे उतना उसका संवर्धन और रक्षण भी करेंगे। विकास के लिये प्रकृति के प्रयोग करने के साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण भी करेंगे।

### प्रस्तावना:—

पर्यावरण प्रदूषण ने विश्व—मानव को सोचने के लिए विवश कर दिया है। समय रहते यदि नहीं चेते तो इसका दुष्परिणाम हमें भोगना होगा। पर्यावरण को प्रकृति संतुलित रखती है यदि प्रकृति के इस स्वाभाविक नियम में हम छेड़छाड़ करने लगते हैं तो प्रकृति सन्तुलन कायम करने में असमर्थ हो जाती है। पानी स्वतः बहता है धरती का पानी खींच कर अपने उपयोग में लेते हैं धरती का वह स्थान स्वतः पानी से भर जाता है। यदि हम धरती का सारा पानी खींच लेने की भावना रखेंगे तो उसकी पूर्ति असंभव होगी। प्रकृति वृक्षों को उगाती, बढ़ाती और उसकी रक्षा करती है हम वृक्षों को काट डालने का अभियान बनाकर विनाश की ओर बढ़ेंगे। तो प्रकृति कितनी रक्षा करेगी, इससे प्रकृति का सन्तुलन बिगड़ जाता है। प्रगति की ओर बढ़ने का मतलब यह नहीं एक निर्माण के लिये दूसरे का विनाश कर दें।

इस पर अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो इस प्रदूषण के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं बच पायेंगे, जिससे आनेवाले समय में यह हमारे विनाश का कारण बन जायेगा। इसलिए यह काफी आवश्यक है, जब हम अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हए सतत विकास के लक्ष्य को पाने का प्रयास करें। सतत विकास स्थिरता के तीन स्तंभों पर टिका हुआ है—आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक यह तीन चीजे इसकी आधारशिला हैं। पर्यावरणीय स्थिरता का तात्पर्य वायु, जल और जलवायु से है। सतत विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू उन गतिविधियों या उपायों को भी अपनाना है। जो स्थायी पर्यावरणीय

CORRESPONDING AUTHOR:	RESEARCH ARTICLE
<b>Dr. Banshidhar</b> Assistant Professor Shree Shraddhanath PG College, Todi (Gudhagorji), Jhunjhunu. Rajasthan. Email: dr.jhahria1978@gmail.com	

संसाधनों में मदद कर सके। जिससे ना केवल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे बल्कि आनेवाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर सकेंगे।

### पर्यावरण और सतत विकास:-

सतत विकास की अवधारणा १९८७ में बनी बर्टलैंड कमीशन से ली गयी है। इस वाक्यांश के अनुरूप सतत विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत वर्तमान की पीढ़ी अपनी जरूरतों को पूरा करे, लेकिन इसके साथ ही संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा सुनिश्चित करे। जिससे आने वाले समय में भविष्य की पीढ़ी के मांगों को भी पूरा किया जा सके। २०१५ के यूनाइटेड नेशन सतत विकास शिखर सम्मेलन ( यू.एन. सस्टेनबल डेवलपमेंट समिट) में विश्व प्रमुखों ने सतत विकास के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

### पर्यावरण प्रबंधन:-

‘मानव तथा पर्यावरण के मध्य सम्बन्ध सुधार की प्रक्रिया ही पर्यावरण प्रबंधन है।’ मानव और प्रकृति के बीच जब सम्बन्ध मधुर होंगे तो प्रकृति से जितना हम लेंगे अथवा जितना दोहन करेंगे उतना उसका संवर्धन और रक्षण भी करेंगे। प्रकृति के साधनों का प्रयोग हमें विवेक पूर्वक करने की आवश्यकता है।

### पर्यावरण प्रबंधन के उद्देश्य:-

विद्वानों के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

- १) प्राकृतिक संसाधनों के दाहे न और उनके उपयोग को एक सीमा तक करना जिससे प्राकृतिक सन्तुलन न बिगड़े।
- २) अवक्रमित पर्यावरण का पुनर्जनन करना तथा प्रकृति के साधनों को जो नष्ट कर डाले गये हैं उनका नवीनीकरण करना।
- ३) प्राकृतिक प्रकोपों के प्रभावों को कम करना। प्राकृतिक संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद जो अपशिष्ट बच जाये उनका पुनर्चक्रण तथा पुनः प्रयोग के माध्यम से प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपभोग करना।
- ४) योजनाओं और कार्यक्रमों का पर्यावरणीय दृष्टि से मूल्यांकन करना। उत्पादन की वर्तमान प्राद्यौगिकी के उपयोग पर फिर से विचार करना जिससे वह प्रदूषण मुक्त हो जाये। पर्यावरण की रक्षा के लिए नियमों और कानूनों की व्यवस्था तथा उनका कड़ाई से पालन।

**सारांशतः** पर्यावरण बोध पैदा करके जन चेतना लानी चाहिए। पर्यावरण के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध की आवश्यकता है। उत्पादन तकनीक को विकसित करके संसाधनों का प्रबंधन करना होगा। विज्ञान और बौद्धिक कुशलता का विकास करना होगा। पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करना होगा। प्रदूषण नियंत्रण करना होगा। राजनीतिक और प्रशासनिक सहयोग मिलना चाहिए। सांस्कृतिक आयामों का नियमन करना होगा। तभी सही अर्थों में पर्यावरण प्रबंधन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र तथा उपागम: पर्यावरणीय प्रबंधन के उपागम निम्नांकित हैं—

#### **समग्रतावादी:**

इसमें संसाधनों के नियोजन के समय पैदा होने वाली सभी पारिस्थितिकी समस्याओं पर विचार किया जाता है और उनके निदान के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। इसमें काफी धन और समय लगता है।

#### **एकल उपागम:**

इसमें पारिस्थितिकी समस्याओं पर आंशिक और अल्पकालिक चिन्तन और समस्याओं का समाधान किया जाता है।

- वन्य जीवों का प्रबन्धन
- मत्स्य संरक्षण का प्रबन्धन
- जल प्रबन्धन
- मृदा प्रबन्धन
- उत्पादन तकनीक और संसाधन
- वन प्रबन्धन आदि

#### पर्यावरण प्रबन्धन के क्षेत्रीय झुन्झुनू जिले में योजना :

- 1) पर्यावरण की समस्यायें कुछ क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित कुछ राष्ट्रीय और कुछ विश्वस्तरीय होती हैं इनके सामाधान के लिए चार स्तरों पर कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
- 2) स्थानीय प्रबन्धन / महानगरों में प्रदूषण की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए।
- 3) क्षेत्रीय प्रबन्धन—इन समस्याओं का निराकरण क्षेत्रीय आधार पर होना चाहिए। जैसे चम्बल घाटी में मृदाक्षरण, ब्रह्मपत्र की बाढ़ समस्या तथा कोसी नदियों की बाढ़ समस्याएं।
- 4) राष्ट्रीय प्रबन्धन—राष्ट्र स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रबन्धन की आवश्यकता होती है जैसे वन संवर्धन, मृदा की समस्या, ऊर्जा संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण आदि के लिए राष्ट्र स्तर पर नीति बनानी चाहिए।
- 5) अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्धन विश्व की समस्याओं को सुलझाने के लिए सभी देशों को मिलकर कार्य करना होगा। जैसे वायुमंडलीय प्रदूषण की समस्या, आणविक युद्ध से निजीकरण की समस्या, जलवायविक समस्या, ओजोन परत के क्षरण की समस्या, हरित गृह प्रभाव के भी समस्या, जैविक विविधता के नष्ट होने की समस्या।

#### महत्वपूर्ण सुझाव:—

#### जिले में पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण एवं पर्यावरण

जिले में पर्यावरण के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित सुझावों को अपनाकर कुछ हद तक समस्या का निराकरण किया जा सकता है। जल प्रबंधन हेतु, सुझाव घरेलु अथवा व्यक्तिगत स्तर पर कृषि क्षेत्र स्तर पर आधौगिक स्तर पर सामुदायिक स्तर पर।

#### वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाय :

कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए जनसंख्या शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए वाहनों में इंधन से निकलने वाले धुएं को ऐसे समायोजित निधर्म चल्हे व सौर ऊर्जा की तकनीक को प्रोत्साहित करना चाहिए। वनों की हो रही अन्धाधुन्ध अनियंत्रित कटाई को रोका जाना चाहिए। शहरों—नगरों में अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु सीवरेज सभी जगह होनी चाहिए।

#### भूमि प्रदूषण नियंत्रण हेतु सुझाव:

भूमि के क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण, बांधा—बंधियां बनाये जाने चाहिये। नवीन कीटनाशकों का विकास किया जाये। कृषि कार्यों में जैविक खाद व दुबर्ल कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भूमि कटाव को रोका जाना। आधौगिक इकाईयों से उत्सर्जित कचरे को ठिकाने लगाने के लिए उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। कचरा निस्तारण के लिए नगर पालिकाओं के सख्त नियम बनाये जाने चाहिए। कृषि अवशेषों को खेतों में न जलाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाना चाहिए।

#### अन्य उपाय:— जन्म दर नियंत्रण

वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण निति एवं कानूनों का निर्माण वनों को नष्ट होने से बचाना पर्यावरण शिक्षा से लोगों में जागरूकता लाना।

**निष्कर्ष:—**

सारांशतः पर्यावरण बोध पैदा करके जन चेतना लानी चाहिये। पर्यावरण के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध की आवश्यकता है। उत्पादन तकनीक कासे विकसित करके संसाधनों का प्रबंधन करना होगा। विज्ञान और बौद्धिक कुशलता का विकास करना होगा। पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करना होगा। प्रदूषण नियंत्रण करना होगा। राजनीतिक और प्रशासनिक सहयोग मिलना चाहिए। सांस्कृतिक आयामों का नियम करना होगा। तभी सही अर्थों में पर्यावरण प्रबंधन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

**संदर्भ:—**

- 1) Arndt, H. W., (1981) - "Economic development: a semantic history," Economic Development and Cultural Change, Vol. 29, No. 3, pp. 457-466
- 2) Barbier, E. B., (1987) – "The concept of sustainable economic development," Environmental Conservation, Vol. 14, No. 2 (1987), pp. 101-110.
- 3) Bartelmus, P. (1986) Environment and Development (London: Allen & Unwin,).
- 4) Blaikie, P., (1985) Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries (London: Longman).
- 5) Brandt Commission, North-South (1980): A Programme for Survival (London: Pan Books).
- 6) Brown, L. R., (1981) Building a Sustainable Society (New York: W. W. Norton).
- 7) Chambers, R., (1988) - Sustainable Livelihoods: An opportunity for the World Commission on Environmental and Development (Brighton, UK: Institute of Development Studies, University of Sussex,).
- 8) Charoenwatana, T., and A. T. Rambo, (1988) "Preface," in T. Charoenwatana and A. T. Rambo (Eds.), Sustainable Rural Development in Asia (Khon Kaen, Thailand: KRU-USAID Farming Systems Research Project, Khon Kaen University and Southeast Asian Universities Agroecosystem Network), pp. viiX.
- 9) Chong, H.G., (2008), "The Environmental Management System as a Competitive Advantage Tool for Organizations", The Journal of Accounting and Finance, The Research Development Association, Jaipur, October-March, Vol.22, No. 1, pp. 71-78.
- 10) Clark, W. C., and R. E. Munn (Eds.), (1986) - Sustainable Development of the Biosphere (Cambridge: Cambridge University Press).
- 11) Committee on Agricultural Sustainability in Developing Countries (1987) -The Transition to Sustainable Agriculture: An agenda for AID (Washington,DC: International Institute for Environment and Development).

